सतना | शुक्रवार | 19 जून 2026 | वर्ष 27 | अंक 286 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

जनहित के प्रहरी 1934 से

5 शिक्षा-रोजगार मुद्दे पर एकजुट हों युवा : राहुल

6 अकाल तख्त के निशाने पर भगवंत मान

7 भारत-यूके सीटीए 15 जुलाई से लागू

11 रॉबर्टा मोरेटी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

समझौते पर किये हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने ऑनलाइन दी स्वीकृति

पेरिस 18 जून. अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिया. इस समझौते पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्सेल्स पैलेस में दस्तखत किये, जबकि ईरान के राष्ट्रपति पजशकियान ने तेहरान में हस्ताक्षर किये. दोनों नेताओं के हस्ताक्षर के बाद भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह पांच बजे से यह समझौता प्रभावी हो गया.

फ्रांस के राष्ट्रति इमैनुएल मक्रों ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रम्प के इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए वीडियो पोस्ट करते हुए बुधवार को लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप ने आज रात वर्सेल्स में ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये. यह समझौता हमेशा रहने वाली शांति का रास्ता बनाता है और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की इजाजत देता है. यह हमारे देशवासियों के लिए सही दिशा में एक जरूरी कदम है जिससे जल्द ही एनर्जी की कीमतों में कमी आएगी.

ईरान-अमेरिका और इजराइल के बीच जारी तनावपूर्ण युद्ध ने पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है. ऊर्जा ढांचे पर हमलों, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई चेन बाधित होने से कई देशों की अर्थव्यवस्था दबाव में आ गई है.

समझौता के प्रमुख बिंदु....

- रिपोर्ट के अनुसार 14 सूत्रीय समझौते में कहा गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे.
- साथ ही इसमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर के कोष का प्रावधान किया गया है हालांकि अमेरिका के लिए इसमें योगदान देना अनिवार्य नहीं है.
- यह समझौता अमेरिका-ईरान और इज़रायल के बीच टकराव शुरू होने के चार महीने बाद हुआ है.
- ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को प्रदर्शन-आधारित बताया है, जिसका मतलब है कि ईरान को तभी फायदा होगा जब वह अपने वादों का पालन करेगा.

ट्रंप की एच-1बी वीजा और यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी

- ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका को भारतीय टैलेंट की जरूरत है और आने वाले समय में एच-1बी वीजा के तहत अधिक भारतीयों को अवसर देने की कोशिश की जाएगी.
- रूस से तेल खरीद को लेकर ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि किसी भी देश, खासकर भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं है और सभी देशों को अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा खरीदने की स्वतंत्रता है.
- उन्होंने बताया रूसी तेल खरीद की मोहलत समाप्त हो चुकी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ने की संभावना है.
- यूक्रेन युद्ध पर ट्रम्प ने दावा किया कि वे इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करेंगे.

युद्ध में अमेरिका का कितना हुआ नुकसान

- अमेरिका का सैन्य खर्च मई 2026 तक लगभग 29 अरब डॉलर तक पहुंच गया.
- अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगभग 210 अरब डॉलर का अप्रत्यक्ष नुकसान.
- एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट को युद्ध में क्षति पहुंची, साथ ही एफ-15 ई स्ट्राइक ईगल, रिफ्यूलिंग टैंकर, एमक्यू -9 रीपर और एमक्यू-4सी ट्राइटन ड्रोन और विमान भी प्रभावित हुए.

ईरान-अमेरिका जंग से नुकसान

- 40 दिनों में देश को लगभग 270 अरब डॉलर (करीब 25 लाख करोड़) का नुकसान हुआ.
- करीब 1,22,000 इमारतें इस संघर्ष में नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं.
- 307 अस्पताल क्षतिग्रस्त होने और दवा कीमतों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है.
- इजराइल पर 650 मिसाइलें दागीं जिससे हजारों इमारतों को नुकसान हुआ है.

एक नजर में

एनएसए डोभाल के न्योते पर भारत आएंगे वांग यी

नई दिल्ली, 18 जून. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी 22 से 23 जून तक भारत का दौरा करेंगे. यह दौरा ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और उच्च प्रतिनिधियों की 16वीं बैठक में भाग लेने के लिए हो रहा है. चीनी विदेश मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी जारी की है.

ईपीएफ को 8.25% की दर से ब्याज प्रस्ताव मंजूर

नयी दिल्ली, 18 जून. कर्मचारी भाविष्य निधि योजना (ईपीएफओ) के अंशधारकों को उनके ईपीएफ खाते में 2025-26 के दौरान जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत की दर से ब्याज के भुगतान को सरकार ने मंजूरी दी है. यह जानकारी गुरुवार को यहां सूत्रों ने दी और कहा कि ईपीएफ की जमाओं पर ब्याज की राशि इस माह खातों में हस्तांतरित की जा सकती है. गौरतलब है कि गत 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर ब्याज 8.25 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया था और इसे अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था. सूत्रों ने कहा कि सीबीटी के निर्णय को अनुमादित कर दिया गया है. यह लगातार तीसरा वर्ष है जब इस ब्याज दर को 8.25 प्रतिशत के इसी स्तर पर बरकरार रखा गया है।

गुस्ताखी माफ

मैसी अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाकर, वर्ल्ड कप्स में सर्वाधिक गोल करने वाले संयुक्त स्कोरर बने!

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उलटफेर

नई दिल्ली, 18 जून. राज्यसभा चुनावों में झारखंड में क्रॉस वोटिंग का बड़ा असर देखने को मिला, जहां कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार तथा उद्योगपति परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज की. झारखंड की दो सीटों में से एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम ने भी जीत हासिल की. वहीं दूसरी सीट पर मुकाबला कांग्रेस और एनडीए समर्थित उम्मीदवार के बीच था, जिसमें क्रॉस वोटिंग निर्णायक साबित हुई. झारखंड विधानसभा के सभी 81 विधायकों ने मतदान किया. नाथवानी को 28 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को 20 वोट प्राप्त हुए.जेएमएम के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले. मतदान के दौरान तीन वोट अमान्य घोषित किए गए, जिनमें बीजीपी के दो और कांग्रेस का एक वोट शामिल था राजनीतिक समीकरण के अनुसार, बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास विधानसभा में 24 विधायक हैं, जबकि बहुमत के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है.

इसके बावजूद क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक समर्थन के कारण एनडीए समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली. देशभर में 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए. झारखंड और मिजोरम की सीटों पर मतदान हुआ, जबकि बाकी राज्यों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ. कुल परिणामों में एनडीए को 19 सीटें मिलीं, जबकि इंडिया ब्लॉक को 6 सीटों पर सफलता मिली.

उद्धव की मीटिंग में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे

मुंबई, 18 जून. महाराष्ट्र के प्रमुख सियासी दल और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के भीतर एक और विभाजन की गुरुवार को उस समय प्रभावी रूप से पुष्टि हो गई, जब पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपकर अपने समूह का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय करने की मांग की.

इन छह बागी सांसदों में संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी-अजा) और ओमप्रकाश उर्फ ओम राजे निंबालकर (उस्मानाबाद) शामिल हैं. इस गुट के बगावत के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में श्री उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहने वाले तीन सांसद अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य) और राजाभाऊ वाजे (नासिक) ही बचे हैं. इस राजनीतिक संकट के बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व ने पार्टी के संसदीय विंग पर नियंत्रण का दावा करने के बागियों के प्रयास का मुकाबला करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया. शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य सचेतक ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है. शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और संसदीय दल के नेता संजय राउत ने श्री सावंत और श्री देसाई के साथ बुधवार को बिरला से मुलाकात की थी. अरविंद सावंत ने ओम बिरला को लिखे एक पत्र में अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे पार्टी की आधिकारिक स्थिति सुने बिना किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दें. उन्होंने लिखा : शिवसेना (यूबीटी) सदन में अपने विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले एक एकल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना जारी रखे हुए है.

शिवसेना (यूबीटी) में टूट की पुष्टि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का सीएम मोहन यादव ने किया स्वागत

इंदौर, 18 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मध्यप्रदेश आगमन हम सबके लिए गर्व का विषय है. प्रदेश की आर्थिक राजधानी और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की नगरी इंदौर में राष्ट्रपति मुर्मु का आत्मीय स्वागत और अभिनंदन है.

आईसीएआई ने सीए में नूर सिंगला ने किया टॉप

नई दिल्ली, 18 जून. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल 2026 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. इस परीक्षा में देशभर से शामिल हुए अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया, जिसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट जारी किया गया.उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर के माध्यम से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

परिसीमन की बिसात | बंगाल के बाद महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश में भी बगावत की सुगबुगाहट तेज

क्षत्रपों का कुनबा बचाने की जद्दोजहद

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 18 जून. देश की राजनीति में इन दिनों एक अभूतपूर्व हलचल देखी जा रही है, दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों में मौजूद क्षेत्रीय क्षत्रपों द्वारा अपने कुनबे को बचाने की जद्दोजहद राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी राजनीतिक उठा-पटक की ओर इशारा कर रही है. ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यह है कि क्या एक साथ कई राज्यों में विपक्षी किलों का इस तरह दरकना केवल संयोग है? या किसी सुविचारित राजनीतिक चक्रव्यूह का हिस्सा है?

राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि जिस तरह से टीएमसी में मचे घमासान और उसके सांसदों के एक बड़े धड़े द्वारा अलग संसदीय समूह बनाने की घोषणा के तुरंत बाद, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में भी बगावत की तेज सुगबुगाहट सामने आई है. इतना ही नहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सियासत में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों द्वारा सपा के भीतर टूट के दावे किए जा रहे हैं उसको किसी सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता है.

ऐसे में ज्यादातर राजनीतिक जानकार यह कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे एक सुनियोजित योजना के तहत भाजपाई रणनीतिकारों द्वारा इसे हवा दी जा रही है. चर्चा है कि दीर्घकालिक रणनीति के तहत सरकार अपनी ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है. हालांकि वर्तमान परिदृश्य में, लोकसभा में भाजपा नेतृत्व वाली राजग के पास बहुमत तो है, लेकिन संविधान संशोधनों जैसे बड़े फैसलों के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा दूर है. ऐसे में विपक्षी सांसदों की यह बगावत और उनका झुकाव परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सत्ता पक्ष की ओर होना, निश्चित रूप से संसद में सरकार की संख्या बल को ऐसी ताकत दे सकता है, जो साधारण विधायी प्रक्रियाओं से परे हो. (शेष पेज 2 पर)